



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2004/फाल्गुन 8, 1925

No. 53]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2004/PHALGUNA 8, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2004

सं. 53 (आर ई 2003)/2002—2007

फा. सं. 01/94/180/18/पीएन/एम 04/पी.सी.-IV.—निर्यात आयात नीति 2002—2007 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

1. पैराग्राफ 5.3.2 के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाता है :

तथापि, सेवा प्रदायक क्षेत्राधिकार प्राप्त उत्पाद कर प्राधिकारी अथवा स्वतंत्र सनदी अभियंता से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं जो इस बात की पुष्टि करे कि सेवा प्रदायक के परिसर में अचल पूंजीगत माल अधिष्ठापित किया गया है।

2. पैराग्राफ 5.3.4 (iii) के पहले वाक्य के बाद एक नया वाक्य जोड़ा जाएगा :

तथापि, सेवा प्रदायक या तो क्षेत्राधिकार प्राप्त उत्पाद कर प्राधिकारी अथवा स्वतंत्र सनदी अभियंता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें इस तथ्य की पुष्टि की गई हो कि आयात पूरा होने की तारीख से छह महीने के भीतर लाइसेंसधारक के रिकार्ड में कलपुर्जों की सूची को ले लिया गया है।

3. पैराग्राफ 5.11.1 की अंतिम पंक्ति में आने वाला "चौड़ा" शब्द (सार्वजनिक सूचना सं. 42 दिनांक 28-1-2004 द्वारा यथाअधिसूचित) को "बोर्ड" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. ई पी सी जी लाइसेंसों की क्लबिंग से संबंधित पैराग्राफ 5.18.3 के दूसरे वाक्य को निम्नलिखित वाक्य से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

क्लब किए गए लाइसेंस की निर्यात दायित्व अवधि क्लब किए गए लागत बीमा भाड़ा मूल्य/क्लब किए गए बचाए गए शुल्क की राशि, जैसा भी मामला हो, लागू नीति के अनुसार होगा।

5. पैराग्राफ 5.18.5 और 5.18.6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

5.18.5 क्लब किए गए लाइसेंस हेतु बरकरार रखा जाने वाला औसत निर्यात दायित्व क्लब किए गए लाइसेंसों पर पृष्ठांकित उच्चतम औसत निर्यात दायित्व के अनुसार होगा।

5.18.6 ई पी सी जी लाइसेंस, जिसकी बढ़ाई गई निर्यात दायित्व अवधि, यदि कोई हो, सहित निर्यात दायित्व अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, हेतु क्लबिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. सार्वजनिक सूचना सं. 42 दिनांक 28-1-2004 में शामिल पैराग्राफ 5.18.7 को हटा दिया गया है।

7. "कम्प्यूटर, कम्प्यूटर उप सिस्टम और ई पी सी जी के अन्तर्गत आने वाले सेवा उपकरण सहित पूंजीगत वस्तुओं हेतु लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन प्रपत्र" से संबंधित परिशिष्ट 9 में उल्लिखित घोषणा/वचनबद्धता के अन्त में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा :
- (vii) मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि आवेदन में आयात के लिए मांगे गए पूंजीगत माल/कलपुर्जों की उत्पाद के उत्पादन के लिए वास्तव में जरूरत है/वस्तुओं के उत्पादन में सहायक हैं या निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए आवेदन में निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु जरूरी हैं। मैं आयातित माल पर 15 प्रतिशत ब्याज सहित यथा लागू सीमाशुल्क वापस करने को वचनबद्ध हूँ तथा किसी भी समय एग्जिम नीति के पैरा 5.4 के नीति उपबन्ध के अनुसार निर्यात उत्पाद से कोई संबंध नहीं रखूंगा।
8. प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैराग्राफ 2.20 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :
- 2.20 अग्रिम लाइसेंस और ई पी सी जी लाइसेंस हेतु बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन करना :
- सीमाशुल्क के माध्यम से वस्तुओं की निकासी से पूर्व सीधे आयात के मामलों में, लाइसेंसधारक सीमाशुल्क प्राधिकारियों से उनके द्वारा निर्धारित तरीके से एक विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी का निष्पादन करेगा। तथापि, स्वदेशी स्रोतों से प्राप्ति के मामले में, नामित एजेंसियों या स्वदेशी आपूर्तिकर्ता से माल प्राप्त करने से पहले लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति धाकर लाइसेंसिंग प्राधिकारी को नीचे यथा निर्धारित रूप में बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा :

क्रम सं.	निर्यातक की श्रेणी	बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता से संबंध प्रावधान
1	2	3
1.	सभी स्तर धारक (पण्य निर्यातक और सेवा प्रदायक दोनों)/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	विधिक वचनबद्धता
2.	विनिर्माता निर्यातक (क) जो केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकरण में पंजीकृत है, और (ख) जिसका न्यूनतम निर्यात कारोबार पिछले वर्ष में 1 करोड़ रुपये और इससे ज्यादा है और (ग) जिसने पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात किया है।	विधिक वचनबद्धता
3.	विनिर्माता निर्यातक (क) जो केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकरण में पंजीकृत है, और (ख) जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अदा किया है।	विधिक वचनबद्धता
4.	उपर्युक्त 1, 2 और 3 उपर्युक्त के तहत न आने वाले अन्य विनिर्माता निर्यातक (मालिकाना और भागीदारी फर्मों के अलावा) (क) जो पिछले 3 साल से निर्यात कर रहे हैं, अथवा (ख) जो पिछले 3 साल के किसी एक वर्ष में निर्यात किए हैं और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं : उत्पाद शुल्क प्राधिकरण के साथ पंजीकृत। अथवा राज्य बिक्री कर प्राधिकरण के साथ पंजीकृत। इन्हें निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे : (iii) सीमाशुल्क परिपत्र सं. 74/2003 दिनांक 21-8-2003 के अनुसार पिछले वर्ष के निर्यातों को प्रमाणित करने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रमाणपत्र और (iv) केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र और उत्पाद नियंत्रण कोड (ई सी सी) अथवा राज्य बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो। उपर्युक्त (क) श्रेणी के लिए इस की आवश्यकता नहीं है।	बॉण्ड जिसके साथ बचाए गए शुल्क के 25 प्रतिशत तक बैंक गारंटी देनी होगी।
5.	विनिर्माता कम्पनियां (मालिकाना फर्म और भागीदारी फर्म जो विनिर्माण भी करती हैं, में भिन्नता दर्शाते हुए) जिन्होंने पिछले सभी तीन वर्षों में निर्यात नहीं किया है लेकिन जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करती हैं : (i) केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकरण में कम्पनी पंजीकृत है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान कर चुकी है (जब तक छूट न दी गयी हो); और (ii) कम्पनी राज्य बिक्री कर कार्यालय में पंजीकृत है और बिक्री कर का भुगतान कर चुकी है (जब तक छूट न दी गयी हो); और (iii) कम्पनी ने लेखा परीक्षित तुलन पत्र की प्रति को प्रस्तुत किया है और संयंत्र और मशीनरी में न्यूनतम निवेश 50 लाख रुपये है।	बॉण्ड जिसके साथ बचाए गए शुल्क के 25 प्रतिशत तक बैंक गारंटी देनी होगी।

1	2	3
6.	पण्य निर्यातक, सभी प्रकार की मालिकाना और भागीदारी फर्म (स्तर धारक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा)	बॉण्ड जिसके साथ बचाए गए शुल्क के 100 प्रतिशत तक बैंक गारंटी देनी होगी।
7.	उपर्युक्त श्रेणी 1 के अलावा सेवा प्रदायक	बॉण्ड जिसके साथ बचाए गए शुल्क के 100 प्रतिशत तक बैंक गारंटी देनी होगी।

तथापि, निर्यातक के जोखिम प्रोफाइल पर आधारित निम्नलिखित दो श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में आने वाले निर्यातक/पण्य निर्यातकों को एक बाण्ड निष्पादित करना होगा जिसके साथ बचाए गए शुल्क के 100 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। इसे, फाइल में कारणों को रिकार्ड करते हुए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित करना होगा जो उप महानिदेशक के रैंक से कम नहीं होना चाहिए।

(क) गम्भीर अनियमितताओं के कारण सीमाशुल्क कार्यालय/डी जी एफ टी/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय के प्रतिकूल नोटिस में आया है।

(ख) लम्बित निर्यात दायित्व की पूर्ति के अनुसार प्रतिकूल कार्य निष्पादन रिकार्ड है।

उन मामलों में जहां स्वदेशी रूप से प्राप्त की गई मदों पर जहां उत्पाद शुल्क शून्य है तो उस उत्पाद पर 15 प्रतिशत ब्याज सहित सीमाशुल्क के 25 प्रतिशत के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। बैंक गारंटी और विधिक वचनबद्धता क्रमशः परिशिष्ट-21 और 21क में निहित शर्तों के अनुसार वैध होगी। निर्यात दायित्व की अवधि के विस्तार के मामले में बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की वैधता में विस्तार करना आवश्यक होगा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस में इस बारे में विशेष तौर पर पृष्ठांकन करना होगा।

उपर्युक्त 3 और 4 श्रेणियों के संबंध में अगर निर्यातक ने पिछले सभी 3 वर्षों में निर्यात नहीं किया है तो बचाए गए शुल्क पर 25 प्रतिशत बैंक गारंटी की शर्त लगाई जाएगी बशर्ते लागत बीमा भाड़ा मूल्य घरेलू कारोबार के 200 प्रतिशत से ज्यादा न हो या आपूर्तियों का पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य/रेल पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 200 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, से ज्यादा न हो। 200 प्रतिशत से अधिक हकदारी वाले लाइसेंस 200 प्रतिशत से अधिक लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए बचाई गई शुल्क राशि पर 100 प्रतिशत बैंक गारंटी के अधीन होगा। तथापि, निर्यात दायित्व को पूरा करने तथा निर्यात/आपूर्ति को पूरा करने के दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर हकदारी को दोबारा लागू कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त सभी मामलों में लाइसेंसधारक को यह घोषणा करनी होगी कि उसे सीमाशुल्क अधिनियम, उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा फेमा/फेरा के तहत दण्डित निष्पादन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त 2, 3 और 4 श्रेणियों के संबंध में तो लाइसेंसधारक को केन्द्रीय उत्पाद के क्षेत्राधिकार में आने वाले अधीक्षक जहां फैक्ट्री स्थित है, द्वारा जारी निर्यात निष्पादन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। संबंधित सीमाशुल्क परिपत्र के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद के क्षेत्राधिकार में आने वाले अधीक्षक को उन एककों को भी निर्यात निष्पादन प्रमाण-पत्र देना होगा जो केन्द्रीय उत्पाद नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं आते। तथापि, ई पी सी जी योजना के अन्तर्गत कार के आयात/घरेलू खरीद के लिए 100 प्रतिशत बैंक गारंटी देनी होगी केवल स्तर धारकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों को छोड़कर जो उपर्युक्त शर्तों के अनुसार बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे।

ऊपर यथा उल्लिखित बैंक गारंटी छूट/रियायत विगत लाइसेंसों के संबंध में भी उपलब्ध होगी जहाँ लाइसेंसधारक पहले बैंक गारंटी दर्ज करा चुका है परन्तु मौजूदा तारीख में लाइसेंसधारक बैंक गारंटी छूट का हकदार है।

9. पैराग्राफ 2.20 के नीचे "कारपोरेट गारंटी" से संबंधित एक नया पैराग्राफ 2.20.1 जोड़ा गया है:

2.20.1 कारपोरेट गारंटी

एक स्तर धारक अथवा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, इस संबंध में संबद्ध सीमाशुल्क परिपत्र के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता के बदले कारपोरेट गारंटी भी जमा कर सकता है। कम्पनी के समूह के मामले में, यदि समूह की एक कंपनी स्तरधारक है, तो इस कम्पनी द्वारा उस कंपनी को कारपोरेट गारंटी दी जा सकती है, जो कि स्तरधारक नहीं है।

10. ऊपर यथा उल्लिखित, पैराग्राफ 2.20 में, पैराग्राफ 4.6 के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। अतः "नए आवेदकों" से संबंधित पैराग्राफ 4.6 हटा दिया गया है।

11. पैराग्राफ 3.18 (ड) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

(ड) शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र के लिए एक समेकित आवेदन कम्पनी के मामले में पंजीकृत कार्यालय और अन्य मामलों में मुख्यालय द्वारा परिशिष्ट-36क में क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि उस लाइसेंसिंग वर्ष, जिसके आधार पर हकदारी का दावा किया गया है, के बाद के लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च होगी। इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एल.मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi the 27th February, 2004

(No. 53 (RE-2003)/2002-2007)

F.No. 01/94/180/18/PN/AM04/PC-IV.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Export and Import Policy 2002-2007 the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures (Vol. I):

1. The following sentence is added at the end of paragraph 5.3.2

However, service providers, can give a certificate either from the jurisdictional Excise authority or from an independent chartered engineer confirming installation of immovable capital goods at the premises of the service provider.

2. A new sentence may be added after the first sentence of the paragraph 5.3.4 (iii) :

However, the service providers, can give a certificate either from the jurisdictional Excise authority or from an independent chartered engineer confirming the inventory of spares taken in record of the licence holder within six months from the date of completion of imports.

3. The word "broad" appearing in the last line of paragraph 5.11.1 (as notified vide Public Notice No 42 dated 28-1-04) should be replaced by the word "board".

4. Second sentence of paragraph 5.18.3 related to clubbing of EPCG licences should be substituted by the following sentence.

The export obligation period of the clubbed licence would be as per the policy applicable for the clubbed CIF value/clubbed duty saved amount, as the case may be.

5. Paragraphs 5.18.5 & 5.18.6 is corrected as below.

5.18.5: The average export obligation to be maintained for the clubbed licence would be the highest of the average export obligations endorsed on the individual licences put up for clubbing.

5.18.6: No clubbing would be permitted for EPCG licences where export obligation period including the extended export obligation period, if any, has already expired.

6. Paragraph 5.18.7 incorporated vide Public Notice-42 dated 28-1-04 stands deleted.

7. The following clause shall be added at the end of the declaration/undertaking given in Appendix-9 pertaining to "Application Form for Grant of Licences for Capital Goods including Computer, Computer Sub Systems and Service Equipment under EPCG".

(vii) I hereby declare that the capital goods/spares sought for import in the application are actually required for use to produce/support the production of the goods or provide the services indicated in the application for fulfilment of export obligation. I undertake to refund the custom duty as applicable with 15% interest on the goods imported & found having no nexus with export product as per Policy provision of para 5.4 of Exim Policy, at any stage.

8. Paragraph 2.20 of Handbook of Procedure Vol. I is amended as follows:

2.20 Execution of Bank Guarantee/Legal Undertaking for advance licence and EPCG licence:

In cases of direct import before clearance of goods through customs, the licence holder shall execute a legal undertaking (LUT)/Bank Guarantee(BG) with the customs authorities in the manner as prescribed by them. However, in case of indigenous sourcing, the licence/certificate/permission holder shall furnish Bank Guarantee/LUT to the licensing authority as prescribed below before sourcing the material from the nominated agencies or indigenous supplier :—

S. Category of Exporter No.	Relevant provisions of Bank Guarantee/LUT
1 2	3
1. All Status holders (both merchandise exporter and service providers)/Public Sector Undertaking (PSUs).	Legal Undertaking (LUT)

1	2	3
2.	Manufacturer exporter	
(a)	Registered with Central Excise authority and	Legal Undertaking (LUT)
(b)	Having a minimum export turn-over of Rs. 1 Crore and above in the preceding year, and	
(c)	Having exported during the previous two financial years.	
3.	Manufacturer Exporter	
(a)	Registered with Central Excise Authority and	Legal Undertaking (LUT)
(b)	Having paid Central Excise Duty of Rs. 1 Crore or more during the preceding financial year.	
4.	Other Manufacturer Exporter not covered under 1, 2 and 3 above (except Proprietorships and Partnership firms)	Bond supported by Bank Guarantee to the extent of 25% of duty saved.
(a)	exporting for last 3 years, or	
(b)	exporting in any of the last 3 years and satisfying the following conditions:	
	Registered with Excise Authorities,	
	or	
	Registered with State Sales Tax Authorities;	
	Shall be required to furnish :	
(i)	A Central Excise certificate certifying preceding years exports as per customs Circular No. 74/2003 dated 21-8-2003, and	
(ii)	Registration Certificate and Excise Control Code (E.C.C.) Number issued by Central Excise Authorities or Registration Certificate issued by State Sales Tax Authorities, as the case may be. This provision is not required for category (a) above.	
5.	Manufacturing companies (as distinguished from Proprietorship and Partnership firm, who may also be manufacturers) having not exported in each of the preceding three licencing years but fulfilled the following criterion :	Bond supported by Bank Guarantee to the extent of 25% of duty saved.
(I)	The company is registered with Central Excise Authorities and has paid Central Excise duty (unless exempted); and	
(II)	The company is registered with State Sales Tax Authorities and has paid sales tax (unless exempted); and	
(III)	The company furnishes copy of their audited balance sheet; and the minimum investment in plant and machinery must be Rs. 50 lakhs.	
6.	Merchant Exporter, all types of Proprietorship and Partnership firms (Other than Status Holders/PSUs)	Bond supported by Bank Guarantee to the extent of 100% of the duty saved.
7.	Service providers other than those in category 1 above.	Bond supported by Bank Guarantee to the extent of 100% of the duty saved.

However, Manufacturer/Merchant Exporters falling under any of the following two categories based on risk profile of the exporter are required to execute bond supported by Bank Guarantee to the extent of 100% of the duty saved amount. This can be prescribed by the Head of the office not being below the rank of Deputy Director General of Foreign Trade by recording the reasons in writing.

- Have come under the adverse notice of Customs/DGFT/Central Excise for serious irregularities;
- Having adverse track record in terms of fulfillment of pending export obligation.

In cases where the Excise Duty is nil on the items of indigenous procurement, the Bank Guarantee furnished would be for 25% of the basic Customs Duty with 15% interest on the same product. The Bank Guarantee and LUT should be valid as per the terms and conditions incorporated in the Appendix-21 and 21A respectively. The validity of the Bank Guarantee/LUT is required to be extended in case of extension in export obligation period. Specific endorsement to this effect shall be made in the licence by the licencing authority.

In respect of categories 3 & 4 above, if the exporter has not exported for all the 3 preceding years, 25% Bank Guarantee condition shall be imposed on the duty saved amount provided the CIF value does not exceed 200% of the domestic turnover or 200% of FOB/FOR value of supplies, whichever is higher. Licence beyond 200% entitlement shall be subject to 100% BG on the duty saved amount for the CIF value exceeding 200% entitlement. However the entitlement may be re-credited on production of documentary evidence showing fulfillment of export obligation and realization of export/supply proceed.

In all the above cases, the licensee is required to furnish declaration to the effect that they have not been penalized under the Customs Act, Excise Act, Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 and FEMA/FERA. In respect of categories at SI no. 2, 3 and 4 above, the licensee would be required to submit the Export Performance Certificate issued by Jurisdictional Superintendent of Central Excise where the factory is located. As per the relevant Customs Circular, the Jurisdictional Superintendent of Central Excise will issue Export Performance Certificate even in respect of units which are not in Central Excise Control. However, for import/domestic procurement of car under EPCG scheme, 100% Bank Guarantee will be required to be furnished except in case of status holders/PSUs who will furnish Bank Guarantee/LUT as per aforesaid conditions

Bank Guarantee exemption/relaxation as mentioned above shall also be available in respect of past licences where licence holder had earlier filed Bank Guarantee but as on date the licence holder is entitled for Bank Guarantee exemption.

9. A new paragraph 2.20.1 related to "Corporate Guarantee" is added below paragraph 2.20 below:

2.20.1 Corporate Guarantee

A Status holder or a PSU may also submit Corporate Guarantee in lieu of Bank Guarantee/LUT in terms of the provisions of relevant Customs Circular in this regard. In case of a group company, if one company of a Group is a status holder, Corporate Guarantee may be given for another company by this company, which is not a status holder.

10. The provision of Paragraph 4.6 has been incorporated in the paragraph 2.20 as mentioned above. So, the paragraph 4.6 related to "New Comers" stands deleted.
11. Paragraph 3.18(c) is amended as under :
- (e) A single consolidated application for the duty free credit entitlement certificate shall be filed with the Jurisdictional regional licensing authority in Appendix-36A by the Registered office in case of a company and Head Office in case of others. The last date for filing of such application shall be 31st March of the licencing year succeeding the licencing year on the basis of which entitlement is claimed.

This issues in the public interest.

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade